CMYK

Android App
Download

साप्ताहिक
क्रांति भास्कर

सोमवार
23.10.2017
वर्ष.06
अंक.39
पेज.8
रु.5.00

भ्रष्टाचार, भाईगीरी, हफ्ता-वसूली और माफियागिरी पर अंकुश लगाने में प्रशासक प्रफुल पटेल भी फैल!

चंद पत्रकारो को सरकारी विज्ञापन का लालच देने से, सच्चाई छुपती नहीं प्रशासक महोदय।

दमन में, भ्रष्टाचार, भाईगीरी, माफियागिरी, हफ्ता-वसूली और शराब-तस्करी करने वाले, प्रशासक प्रफुल पटेल की गोद में नहीं बैठे है तो क्या प्रशासक प्रफुल पटेल उनकी गोद में बैठे है? यह सवाल इस लिए है क्यों की प्रशासक पद पर प्रफुल पटेल की नियुक्ति के बाद, अब तक ना ही दमन में भ्रष्टाचार बंद हुआ, ना ही भाईगीरी बंद हुई, ना ही माफियागिरी और ना ही हफ्ता-वसूली, चंद छोटे-मोटे मामलों में अवश्य शराब तस्करो पर गाज़ गिरी, लेकिन उस गाज़ का श्रेय भी गुजरात प्रशासन को मिला। दमन प्रशासन ने तो गुजरात पुलिस की छापे मारी के तुरंत बाद, उन शराब कारोबारियों को भी पुनः शराब बेचने की स्वीकृति दे दी, जिनके खिलाफ गुजरात में दर्जनों मामले लंबित है।

१० आई-ए-एस, ४ आई-पी-एस, ३ आई-एफ-एस और दर्जनों दानिक्स एवं दानिप्स अधिकारियों की उपस्थिती के बाद भी व्यस्वथा अस्थ-व्सस्थ!

संध प्रदेश दमन-दीव व दानह में इस वक्त प्रशासक प्रफुल पटेल के पास, 10 आई-ए-एस अधिकारी है, 4 आई-पी-एस अधिकारी है, 3 आई-एफ-एस अधिकारी है तथा लगभग 1 दर्जन से अधिक दानिक्स एवं दानिप्स अधिकारी है अब इतने वरीय तथा काबिल अधिकारियों की निगरानी के बाद भी यदि भ्रष्टाचार, अनियमितताएँ, भाईगीरी, माफियागिरी और हफ्ता-वसूली बदस्तूर जारी रहे तो यह दमन-दीव व दानह प्रशासन के लिए चुल्लु-भर पानी तलाशने वाली बात है!

10 IAS	03 IFS
04 IPS	DANICS & DANIPS

क्या आई-बी को नहीं पता भाईगीरी और माफियागिरी के बारे में?

वैसे इतने अधिकारियों के अलावे दमन में आई-बी के अधिकारी भी मौजूद है और इस तरह की जानकारी हांसील करने में आई-बी के अधिकारियों को महरथ हासिल है, प्रशासक महोदय यदि वास्तव में आप भाईगीरी, माफियागिरी और हफ्ता-वसूली की जानकारी से अनभिज्ञ है तो आई-बी के अधिकारियों से इस मामले में तहक़ीक़ात करवाइए!

जिस पर जीतने अधिक आरोप उस पर उतनी ही अधिक मेहरबानी!

अब तक कई कथित भ्रष्ट अधिकारियों पर विकास के नाम पर मेहरबानी दिखा चुके है प्रशासक प्रफुल पटेल।

काम करने की काबिलियत या भ्रष्टाचार करने की काबिलियत पर अतिरिक्त प्रभार?

दानह स्वस्थ्य विभाग के अधिकारी वी-के दास को दमन-दीव का अतिरिक्त प्रभार, दमन-दीव विधुत विभाग के कार्यपालक अभियंता मिलिंद इंगले को, दानह विधुत निगम का अतिरिक्त प्रभार, दमन लोक निर्माण विभाग के अभियंता पंकज पटेल को, दमन नगर निगम तथा जिला पंचायत के कार्यपालक अभियंता का अतिरिक्त प्रभार तथा लोक निर्माण विभाग के कनिय अभियंता बिपिन पवार को दमन आर-टी-ओ का अतिरिक्त प्रभार देने से पहले, प्रशासक प्रफुल पटेल ने इन अधिकारियों के काम करने की काबिलियत को देखा या भ्रष्टाचार करने के बाद बचे रहने की काबिलियत को देख कर यह अतिरिक्त प्रभार दिए गए है? यह सवाल अब दमन-दीव व दानह की प्रबुद्ध जनता के उन मुह पर है, जिन पर प्रशासन अभी तक किसी प्रकार की भय की टेप लगाने में असफल रही!

क्या किसी बच्चे के नेटवर्क से भी कमजोर है प्रशासन का नेटवर्क?

क्या दमन-दीव प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारियों का नेटवर्क एक बच्चे के नेटवर्क से भी कमजोर है? क्यों की दमन के किसी समजदार बच्चे से भी पूछा जाए, तो वह भी तुरंत बता देगा की दमन के किस क्षेत्र में किस भाई का राज है, और किस क्षेत्र में काम करने के लिए किस भाई को नमस्ते करना पड़ेगा?

क्या दमन का फील्ड-पब्लिसिटी विभाग भी चाटुपत्रकारिता प्रेमी है?

हालांकि क्रांति भास्कर ने, भाईगीरी, माफियागिरी और हफ्ता-वसूली जैसे मामलों में इससे पहले भी कई बार प्रमुखता से ख़बरे प्रकाशित की है लेकिन लगता है अब तक प्रशासक प्रफुल पटेल तक क्रांति भास्कर की उन खबरों की कतरने नहीं पहुंची, या फिर दमन-दीव के फील्ड-पब्लिसिटी विभाग को भी केवल चाटुपत्रकारिता वाली खबरों की कतरने जमा करने की आदत लग गई है?

कमाल फोटो का या फोटो वाले का?

क्या सुरेश पटेल तथा केतन पटेल के भाई जिग्नेश पटेल पर प्रशासन केवल इस लिए कार्यवाही नहीं करती है क्यों की वह नेता है? और प्रशासक प्रफुल पटेल के साथ हस्ते हुए फ़ोटो खिचवाते है? तो जरा सोचिए प्रशासक प्रफुल पटेल, प्रशासन के इस रवैये से जनता और अपराधियों में क्या संदेश जाता होगा?

दमन का बच्चा बच्चा जानता जिग्नेश पटेल उर्फ जिग्गुभाई की हफ्ता-वसूली और कारगुजारियों के बारे में और सीबीआई केतन पटेल के यहां पहुँच गई, इसे कहते है कही पर निगाहे कही पर निशाना!

अब तक जांच एर्जेसियों ने कितने मामलों तथा घोटालों में जनता के धन की रिकवरी की?

जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, जिनके खिलाफ जनता की शिकायते है उन पर नजर रखना, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करना, घोटालो तथा भ्रष्टाचार के मामलों में जनता के धन का जितना भी गमन हुआ उसकी रिकवरी करना।

लेकिन दमन-दीव व दानह की जांच ऐजेंसिया मानों मरणासन के बिस्तर पर पड़ी जनता की गढ़ी कमाई पूरी कर रही हो, इतना ही नहीं अधिकारियों की कमी और अतिरिक्त प्रभार से प्रभावित जांच एजेंसियो से तो अच्छा है प्रशासन इस विभाग को बंद कर जनता का वो पैसा तो बचाए जो इन जांच एजेंसियों पर खर्च हो रहा है!

संध प्रदेश दमन-दीव व दानह प्रशासन में ऐसे कई अधिकारी है जो पूर्व में किसी ना किसी घोटाले में तथा भ्रष्टाचार के मामले में पकड़े जा चुके है और निलंबन का स्वाद चख चुके है, अब ऐसे अधिकारियों के हाथों में प्रशासनिक विभागों की बागडोड देकर प्रशासक प्रफुल पटेल किस तरह का और किस किसम का विकास करना चाहते यह तो वही जाने, लेकिन ऐसे अधिकारियों पर प्रशासन की मेहरबानी देखकर जनता का यह सवाल है की क्या प्रशासन के पास इन अधिकारियों के अलावे कोई और विकल्प है ही नहीं या प्रशासन सवय जान-बुझ कर कोई विकल्प तलाशना नहीं चाहिए।

प्रशासक महोदय भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने से पहले, प्रशासक कार्यालय तथा प्रशासनिक विभागों में लंबित पड़ी शिकायतों पर गौर कीजिए और उन अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू कर उन तमाम अधिकारियों को तत्काल निलंबित कीजिए जिनके जांच एवं निलंबन की मांग जनता जनर्धन करती आई है। पिछले कई वर्षों से दमन-दीव व दानह प्रशासन, जनता को उनकी शिकायतों हुई कार्यवाही की जानकारी नहीं दे रही है, क्या सतर्कता विभाग में यदि अधिकारियों की कमी है तो दमन-दीव व दानह के काबिल बे-रोजगारो इस विभाग में नोकरी दीजिए जिससे विभाग ठीक तरह से चल सके।

दमन-दीव व दानह के किसी नेता ने गड़बड़ी की है तो उसका जवाब तो जनता समय आने पर अपने वोट से भी दे सकती है इस लिए राजनेताओं पर गाज़ गिराने के बजाए उन अधिकारियों के माथे पर से अपना हाथ हटाये, जिनके भ्रष्टाचार का कीचड़ आपसे पहले कई अन्य प्रशासकों की सफ़ेद कमीज को धुंधला कर चुका है।

यदि जनता की शिकायते अधिक है और दमन-दीव व दानह सतर्कता विभाग के पास जांच का समय नहीं है तो उन तमाम अधिकारियों की जांच सीबीआई अथवा किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाएँ, आखिर उनका काम ही यही है, तो समय व्यर्थ ना करते हुए जांच की और कदम बढ़ाए और इस देश का पैसा बचाएं।

क्रांति भास्कर इससे पहले भी कई बार भ्रष्टाचार और भाईगीरी के मामलों में प्रशासन की पोल खोल चुकी है और प्रशसन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर चुकी है आगे भी भ्रष्टाचार और भाईगीरी पर अंकुश लगाने के लिए क्रांति भास्कर देश हित में अपनी यह मुहिम जारी रखेगी, चाहे उसे शडियंत्र में फंसा देने की धम्की ही क्यो ना मिले, क्रांति भास्कर प्रशासन अथवा किसी भ्रष्ट अधिकारी की धमकियों से नहीं डरती, बल्कि निडरता से पत्रकारिता करती है, यहां की प्रशासन भले-ही चाटुकारिता की आदि हो चुकी हो, लेकिन क्रांति भास्कर चाटूपत्रकारिता नहीं जानती, बल्कि उन तमाम नोकरशाहों की चूल हिला डालने की कुबत रखती है जिनहोने देश की जनता का धन लूटा।

प्रशासक महोदय, दमन-दीव व दानह का भला करने की बात से जनता भला नहीं होने वाला, वास्तव में यदि जनता का भला करना है तो जनता की शिकायतों पर जांच करें और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करें, वरना भ्रष्टाचार के मामलो में जांच नहीं करने पर, हो सकता है की जनता कल आपकी भी जांच की मांग कर बैठे। शेष फिर।

एक नोटिस बोर्ड ऐसा भी लगाए और जनता का समय एवं पैसा बचाए!

दमन-दीव व दानह प्रशासन यदि भ्रष्टाचार के मामलों में, जनता की शिकायतों पर जांच नहीं करना चाहती अथवा जांच की फ़ाईले दबाकर रखना चाहती है, तो कृप्या प्रशासक प्रफुल पटेल को, सचिवालय के बाहर तथा अन्य सरकारी विभागो एवं कार्यालयों के बाहर, सतर्कता विभाग के नाम पर लगे नोटिस बोर्ड की तरह, जनता के लिए एक और अतिरिक्त बोर्ड भी लगा देना चाहिए, जिसमे लिखा हो की कृप्या भ्रष्टाचार के मामले में भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत करके अपना कीमती समय एवं पैसा खर्च ना करें!

२०-२० वर्षों में अपने कर्मचारियों का विकास नहीं करने वाले अधिकारियों के नाजुक कंधो पर दानह के विकास का भार!

प्रशासन में २० वर्षों से काम कर रहे है, पर पी-एफ आज तक नहीं मिला।

संघ प्रदेश दानह के विकास हेतु, प्रतिवर्ष विकासीय राशि में बढ़ोतरी होती हुई देखी जाती है, संघ प्रदेश दानह के प्रशासक, बड़े बड़े आई-ए-एस अधिकारी तथा विभागीय सचिव व अभियंता प्रत्येक वर्ष विकास की एक नई रूप रेखा का हवाला देते हुए, इसी मंशा में रहते है की किसी ना किसी तरह, इस वर्ष भी विकासीय निधि में पिछले वर्ष की तरह इजाफ़ा हो जाए, तो उन्हे फिर से अपने हिस्से की चांदी काटने का मौका मिले! गरीब जनता और आदिवासियों के विकास का हवाला देकर मांगी गई विकासीय राशि से जन हित में कितना काम होता है इसका अंदाजा आप इस मामले को देख कर लगा सकते है।

क्रांति भास्कर के पास, दानह का एक ऐसा मामला सामने आया है जो दानह प्रशासन के उन तमाम अधिकारियों की भी पोल खोलने के लिए काफी है जो गरीब जनता और आदिवासियों के भविष्य और विकास का हवाला देकर, केन्द्र सरकार से करोड़ो की विकासीय निधि तो प्रतिवर्ष लेते रहे, लेकिन अपने उन कर्मचारियों एवं मजदूरो तक का विकास नहीं कर पाए जो वषी से दानह प्रशासन में डेलीवेजस पर काम कर रहे है।

कई वर्षों से प्रशासन की कामचोरी और आलस्य का खामियाजा भुगत रहे है दानह के सेकड़ों मजदूर।

मामला है दानह के लोक निर्माण विभाग खंड-1 और खंड-2 में काम करने वाले कर्मचारियो का तथा मजदूरो का, इन दोनों विभागो का प्रभार कार्यपालक अभियंता भोया के पास है और इन दोनों विभागो में 300 से अधिक कर्मचारी तथा मजदूर ऐसे है जो कई वर्षों से अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे है और कई वर्षों से विभाग के कार्यपालक अभियंता भोया तथा प्रशासन से यह गुहार लगा रहे है की उन्हे भी उनका हक और अधिकार दे दिया जाए, उन्हे भी नियमुसार नियमित कर दिया जाए और वह तमाम सुख-सुविधाए उपलब्ध कराई जाए जिनके वह हकदार है।

कई कर्मचारी एवं मजदूर तो पिछले 20 वर्षों से डेलीवेजेस पर काम कर रहे है और प्रशासन की कामचोरी और आलस्य का खामियाजा भुगत रहे है, लगभग न्यूनतम वेतन के सहारे अपना एवं अपने परिवार का गुजारा करने वाले इन कर्मचारियों एवं मजदूरो का पी-एफ तक प्रशासन नहीं काटती ऐसी जानकारी क्रांति भास्कर को मिली है।

अब पी-एफ संबन्धित मामलों में क्रांति भास्कर को पता चला कि, डेलीवेजेस पर काम करने वाले किसी मजदूर अथवा कर्मचारी के कार्य का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक हो तथा कर्मचारी एवं मजदूर नियमित हो तथा डेलीवेजेस पर ना हो, तो उसका पी-एफ काटा जाने का प्रावधान बताया जाता है, लेकिन नियमों को तोड़-मरोड़ कर अपनी सुविधा अनुसार रास्ता निकालने वाले अधिकारियों ने कर्मचारियों और मजदूरो का पी-एफ चोरी का भी अजीबो-गरीब रास्ता निकाला है, कर्मचारी और मजदूर का पी-एफ ना काटना पड़े इसके लिए प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष के कार्यकाल का मुज़दूर एवं कर्मचारी से एक नए ऐग्रीमेंट पर हस्ताक्षर ले लिए जाते है, और कर्मचारी एवं मजदूर पिछले कई वर्षों से वार्षिक एग्रीमेंट का दंश झेल रहे है।

दमन-दीव व दानह के सरकारी विभागों में काम करने वाले और ऐसे कितने मजदूर है, जिनहे पी-एफ तथा अन्य मूल-भूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है?

अनियमितता, भ्रष्टाचार और कमाउनीति से फुर्सत मिले तो जरा मजदूरों के बारे में भी सोचिए सलाहकार महोदय।

दानह के ३०० से अधिक कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में!

एक टेण्डर के लिए दर्जनों मीटिंगे करने वाले अधिकारियों के पास क्या सेकड़ों मजदूरों के लिए मीटिंग करने का समय भी नहीं?

दानह के इन दो विभागों में ३०० से अधिक मजदूर परेशान, अन्य विभागों का आलम क्या है जरा पता लागाइए प्रशासक महोदय।

खंड-1 खंड-2

२०-२० वर्षों से प्रतिवर्ष होता रहा, एक वर्ष का एग्रीमेंट!

अब यदि यह सही है तो वापी में स्थित भविष्यनिधि कार्यालय के अधिकारी, दानह में काम करने वाले कर्मचारियों तथा मजदूरो का 20-20 साल से पी-एफ नहीं काटने पर, तथा इस मामले में हुई तिकडमबाजी के लिए किसे दोषी ठहराएँगे यह देखने वाली बात है, क्यो की जब एक ही मजदूर 20-20 साल से सरकारी विभाग में डेलीवेजेस पर नोकरी कर रहा हो और उसी को पी-एफ की सुविधा से वंचित रखा जा रहा हो, तो मजदूरों के हितों की बात करने वाली इस प्रशासन के लिए यह बड़े शर्म की बात है। मजदूर को नियमित करने के बजाए उस पर अनियमित श्रमिक एवं कर्मचारी का ठप्पा लगाने के लिए प्रति वर्ष के कार्यकाल एग्रीमेंट मजदूर के साथ किसी क्षडियंत्र से कम नहीं लगता।

इसी के साथ अब सवाल यह भी है कि भरपूर मेहनत करने वाले इन गरीब आदिवासियों का विकास कब होगा और कैसे होगा? कब इन्हे इनका हक मिलगा और कब यह नियमित किए जाएंगे? इसका जवाब तो विभाग के कार्यपालक अभियंता भोया और प्रशासन के मुख्या प्रशासन प्रफुल पटेल को देना चाहिए, विभागों में काम करने वाले मजदूर अब यह सवाल कर रहे है की यदि किसी निजी कंपनी में भी काम करते तो उनके साथ शायद ऐसा नहीं होता जो इस प्रशासन में हो रहा है।

वैसे दानह की जनता अभियंता भोया की कार्यप्रणाली और कमाउनीति के बारे में भी अच्छी तरह जानती है, लेकिन इस वक्त मामला उन कर्मचारियों और मजदूरो का है जो अपने हकों और अधिकारो से वंचित है और इस मामले में अधिकतर मजदूर तथा कर्मचारियों का यह मानना है कि अभियंता भोया जान-बुझ कर मजबूर, मजदूरो तथा कर्मचारियों को मजदूर ही बनाकर रखना चाहते है, यदि यह सही है तो प्रशासन को इस मामले में जांच करने की आवश्यकता है।

प्रशासक प्रफुल पटेल कृप्या इस विभाग में दोनों आंखे खोल कर ईमानदारी से झाकिए, तो शायद आपको वह तमाम गड़बड़िया और घोटाले भी दिख जाए जो अब तक विकास के नाम पर होते रहे, वैसे कार्यपालक अभियंता भोया के राज में गड़बड़िया और घोटाले कोई नई बात नहीं, पूर्व में भी इस अधिकारी के भ्रष्टाचार की दास्तान पर जांच एजेन्सी महोर लगा चुकी है, यह और बात है कि उस महोर का असर अब तक प्रशासन जनता को नहीं दिखा पाई।

अब प्रशासक प्रफुल पर्टेल को इस की जांच करने की आवश्यकता है की दानह लोक निर्माण विभाग खंड-1 तथा खंड-2 के तर्ज पर दानह तथा दमन-दीव के विभागों में और ऐसे कितने मजदूर है जो डेलीवेजस पर सालों से विभागों में काम कर रहे है और जिनका पी-एफ नहीं काटा जा रहा है, पता यह भी लगाने की जरूरत है की विकास के लिए सेकड़ों मीटिंगे करने वाले अधिकारियों ने इन मजदूरों के हक के लिए मीटिंग करने का समय क्यों नहीं निकाला और क्या कारण है जिसके चलते अब तक यह मजदूर और कर्मचारी प्रशासन की खराब तथा सुस्त कार्यप्रणाली को कोश रहे है शेष फिर।

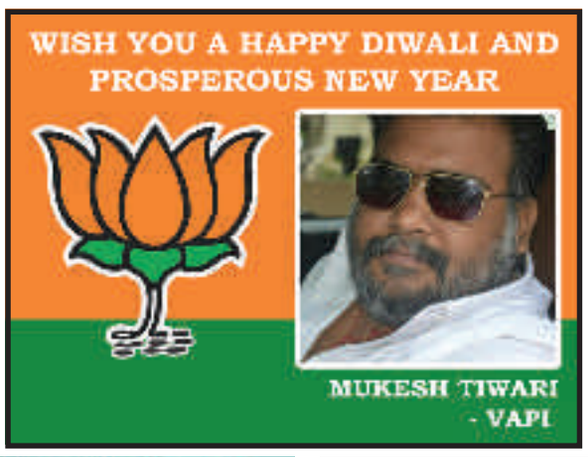

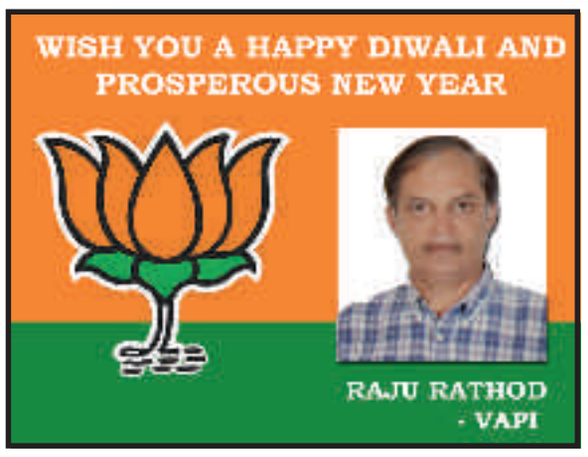

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, चिंटू मांगिलाल जैन, द्वारा ताप्तीलोक पब्लिकेशन, १५२ - १५३ श्रीराम इंडस्ट्रियल इस्टेट, पांडेसरा, सुरत गुजरात से मुद्रित
एवं सी-१०४ मिथुनपार्क - सी, चला-२, चला वापी, जिला वलसाड - गुजरात से प्रकाशित, संपादक चिंटू मांगिलाल जैन - Reg.No.GUJHIN/2012/44382